हादसा | घबराए एक साथी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

मछली मारने गए युवक की करंट से मौत

चिल्हारी नवभारत 16 जून। जिले इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर चौकी के ग्राम अमरपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब भदार नदी में मछली मारने गए एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रमाकांत कचेर (25 वर्ष) निवासी अमरपुर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार रमाकांत अपने कुछ साथियों के साथ भदार नदी में मछली मारने गया था। इसी दौरान नदी में लगाए गए करंट की चपेट में आ जाने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद साथ गए युवक घबरा गए और किसी को सूचना दिए बिना वहां से चले गए।

बताया जाता है कि जब रमाकांत तीन दिनों तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने अमरपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई।

झाड़ियों में मिला रमाकांत का शव

मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी अभिलाष सिंह ने तत्काल जांच शुरू की और रमाकांत के साथ गए साथियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान करने पर उन्होंने पूरी घटना बता दी। साथियों की निशानदेही पर पुलिस ने बेशर्म की झाड़ियों से रमाकांत का शव बरामद किया।

एक साथी ने घबराकर की आत्महत्या

घटना के बाद एक साथी ने संदीप उर्फ बूंदे ढीमर घबरा गया। घटना का खुलासा होने के बाद उसने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, अन्य साथी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं।

नदी में करंट कैसे आया इसकी जांच की जा रही है : सिंह

चौकी प्रभारी अभिलाष सिंह ने कहा कि नदी में करंट कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। फरार साथियों की तलाश जारी है। पूछताछ के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अमरपुर पुलिस ने बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।

नियम को ताक पर रखकर अधिकारी कर रहे अपनी जेबें गरम

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ग्राम पंचायत उमरिया

चिल्हारी नवभारत 16 जून। जनपद पंचायत मानपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उमरिया बकेली इस समय भ्रष्टाचार का मॉडल बनी हुई है। यहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने की ऐसी लूट मची है कि नियम-कायदे रद्दी के टुकड़ों की तरह उड़ाए जा रहे हैं। सरपंच, सचिव और उपयंत्री (इंजीनियर) की त्रिमूर्तियों ने मिलकर पंचायत को अपनी निजी जागीर बना लिया है, जहां गुणवत्ता से समझौता और योजनाओं में बंदरबांट अब आम बात हो गई है।

बता दें कि वनान्चल के बीच बसी यह ग्राम पंचायत में गरीब तबके के हरिजन आदिवासी मजदूर लोग निवासरत है। इन्हें शासन की महात्वाकांक्षी योजानाओं का लाभ नही दिया गया बल्कि अपने चहेतों के ऊपर सरपंच सचिव ने शासन के नियमों को ताक में रख कर शासन की सासकीय राशि का खूब जी भरके दोहन किया है

सीसी रोड नहीं, भ्रष्टाचार की बिछी है परत

पंचायत में निर्माणाधीन सीसी रोड सरकारी मापदंडों की धज्जियाँ उड़ा रही है। मौके पर स्थिति यह है कि न तो सडक़ की चौड़ाई तय मानकों के अनुसार है और न ही इसकी मोटाई। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि सड़क़ निर्माण में जिस रॉयल्टी वाली रेत का उपयोग होना चाहिए था, उसकी जगह तालाब की अवैध रेत खपा दी गई। सरपंच-सचिव ने अपनी जेबें भरने के लिए निर्माण की मजबूती को ही दांव पर लगा दिया है।

प्रशासनिक चुप्पी पर उठे सवाल

जब इस भ्रष्टाचार के खेल पर सरपंच लोकेश कुशवाहा और सचिव मंगलेश्वर शुक्ला से पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। अफसरों और जन प्रतिनिधियों की यह चुप्पी मिलीभगत की ओर इशारा करती है।

एक ही जगह का दो बार भुगतान!

पंचायत में आर्थिक अनियमितता का ऐसा खेल खेला गया जो जांच का सबसे बड़ा विषय है। शासन की गाइडलाइन के विपरीत, एक ही सरपंच के कार्यकाल में एक ही स्थान का दो बार भुगतान निकाला गया। खेल मैदान के सौंदर्याकरण के नाम पर पहले समतलीकरण, गिट्टी और प्लास्टर का भुगतान हुआ, और अब उसी जगह पर पेवर ब्लॉक लगवाकर दोबारा सरकारी राशि डकार ली गई। यह सीधे तौर पर वित्तीय गबन का मामला प्रतीत होता है।

आवास योजना में भी भारी धांधली

भ्रष्टाचार यहीं नहीं थमा, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भारी धांधली उजागर हुई है। सरपंच लोकेश कुशवाहा ने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अपने सगे भाई को ही आवास का लाभ दिलवा दिया, जबकि गाइडलाइन स्पष्ट कहती है कि जनप्रतिनिधि अपने परिजनों को लाभ नहीं दे सकते। गाँव के असली जरूरतमंद आज भी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं और संपन्न लोगों को सरकारी मलाई खिलाई जा रही है।

आवारा पशुओं व डिवाइडरों पर लगाए रेडियम व संकेतक

शहपुरा के युवाओं की अनूठी पहल

शहपुरा नवभारत 16 जून। शहपुरा नगर में सड़क सुरक्षा और पशु संरक्षण को लेकर युवाओं द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। ओंकारा दल करौंदी एवं नगर के युवाओं ने मिलकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा गाय-बैलों के गले में रेडियम युक्त सांकेतिक बेल्ट पहनाए, साथ ही नगर के नवनिर्मित डिवाइडरों पर भी विभिन्न स्थानों पर रेडियम स्टीकर लगाए गए, जिससे रात के समय सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को बेहतर दृश्यता मिल सके।

नगर में लंबे समय से आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आती रही हैं। रात के अंधेरे में पशु दिखाई न देने के कारण कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे पशुओं और लोगों दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है।

रेडियम बेल्ट दूर से ही चमकते हैं-युवाओं द्वारा पशुओं के गले में लगाए गए रेडियम बेल्ट दूर से ही चमकते हैं, जिससे वाहन चालक समय रहते सावधान हो सकेंगे और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। इसी प्रकार नवनिर्मित डिवाइडरों पर लगाए गए रेडियम स्टीकर भी सड़क सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। रात्रि के समय डिवाइडर स्पष्ट दिखाई देने से वाहन चालकों को मार्ग की सही जानकारी मिलेगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

अभिनव पहल की सराहना की जा रही-नगरवासियों ने युवाओं की इस अभिनव पहल की जमकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि यह कार्य नगर परिषद एवं संबंधित ठेकेदारों द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन युवाओं ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए स्वयं आगे बढ़कर इसे पूरा किया। नागरिकों ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि समाज में जनहित के कार्यों के प्रति जागरूकता भी विकसित होगी।

टिकराटोला में जलसंकट गहराया, दो किमी . दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण

जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार

डिंडौरी, नवभारत 16 जून। जिले की ग्राम पंचायत नेवसा के अंतर्गत आने वाले बैगा जनजाति बहुल टिकराटोला में पेयजल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। लंबे समय से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और लिखित आवेदन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की।

ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि टिकराटोला में शासन की नल-जल योजना संचालित तो है, लेकिन योजना का लाभ ग्रामीणों को नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि महीने में केवल एक-दो बार ही पानी की आपूर्ति होती है और तब भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता।

सप्लाई किया जा रहा गंदा एवं दूषित पानी

ग्रामीणों का कहना है कि सप्लाई किया जाने वाला पानी भी गंदा एवं दूषित होता है, जिससे उसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि टिकराटोला बैगा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अधिकांश परिवार आदिम जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। पेयजल की समस्या के कारण महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को प्रतिदिन लगभग दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है।

योजना के दावों की खुली पोल

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में नल-जल योजना के लिए अलग से बोरवेल की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन टिकराटोला में योजना के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

जनजातीय कार्य विभाग की स्थानांतरण सूची जारी

122 शिक्षकों को शिक्षकविहीन शालाओं में पदस्थ किया गया

डिंडौरी, नवभारत 16 जून। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति-2026 के तहत जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी द्वारा जिले के भीतर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची जारी कर दी गई है।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र जाटव ने बताया कि कुल 206 शिक्षक-कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिनमें 145 प्रशासनिक तथा 61 स्वैच्छिक स्थानांतरण शामिल हैं। कलेक्टर के जिला भ्रमण के दौरान यह तथय सामने आया था कि जिले की कई प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं नियमित शिक्षकों के अभाव में अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रही हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए शिक्षकविहीन विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे जिला प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद क्रियान्वित किया गया।

जिले में अब कोई भी प्राथमिक शाला शिक्षकविहीन नहीं

प्रशासनिक आधार पर 122 शिक्षकों का स्थानांतरण कर उन्हें शिक्षकविहीन शालाओं में पदस्थ किया गया है। विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद जिले में अब कोई भी प्राथमिक शाला शिक्षकविहीन नहीं बची है। इससे शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

214 स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदनों का परीक्षण किया गया

ईएचआरएमएस पोर्टल पर प्राप्त 214 स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदनों का परीक्षण किया गया। शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देने के उद्देश्य से इनमें से 61 आवेदनों को स्वीकृत कर स्थानांतरण हेतु पात्र पाया गया। इन स्थानांतरणों को भी कलेक्टर की सहमति के उपरांत अंतिम रूप दिया गया।

काफी कम स्थानांतरण किए गए

जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि इस वर्ष स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही स्थानांतरण नीति के तहत अनुमत अधिकतम संख्या की तुलना में काफी कम स्थानांतरण किए गए हैं, जिससे विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हों।

सभी वर्गों की सहभागिता एवं जनसुझाव से तैयार होगा प्रारूप

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक आयोजित

डिंडौरी, नवभारत 16 जून। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनसुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जनपरामर्श बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उच्च स्तरीय समिति के सदस्य बुधपाल सिंह सामाजिक कार्यकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव एवं विचार प्राप्त किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए बुधपाल सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में किया गया है।

संविधान निर्माण के दौरान हुई थी व्यापक चर्चा

उन्होंने बताया कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति भिन्न होने के बावजूद दोनों का उद्देश्य नागरिकों के कल्याण, समानता एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के दौरान इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी तथा संविधान निमार्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

आमजन के सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में आमजन के सुझाव प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर जनपरामर्श की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शासन की मंशा है कि विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों के नागरिकों की राय प्राप्त कर उसे नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिससे अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी निर्णय लिए जा सकें।

आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी का आरोप

नवभारत, ब्योहारी। ब्योहारी रेलवे स्टेशन एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर आरक्षित टिकटों की कथित कालाबाजारी और यात्रियों से अभद्र व्यवहार के आरोपों ने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता इजराइल खान ने टिकट प्रभारी राजीव गुप्ता एवं काउंटर कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत रेलवे हेल्पलाइन 139 और वरिष्ठ अधिकारियों से की है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए मुंबई जाना था। इसके लिए वह चार यात्रियों का आरक्षण कराने ब्योहारी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पहुंचे। उनका आरोप है कि काउंटर पर मौजूद कर्मचारी नीरज मीणा ने चारों यात्रियों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने की बात कही, जबकि उनके पास तीन यात्रियों के आधार कार्ड उपलब्ध थे। आरोप है कि दस्तावेजों के बावजूद टिकट बनाने से इनकार कर दिया गया और उन्हें कथित रूप से दलाल कहकर अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का कहना है कि आरक्षण फार्म भी फाड़ दिया गया और साफशब्दों में कह दिया गया कि उनकी टिकट नहीं बनाई जाएगी। घटना से आहत होकर उन्होंने तत्काल रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कराई तथा मामले की जानकारी मीडिया को दी।

यात्री से अभद्रता का मामला गरमाया

मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्टेशन पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी की जा रही है और निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है ।जब इस संबंध में टिकट प्रभारी राजीव गुप्ता से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मीडिया से सीधे बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद ही कोई जवाब दिया जाएगा।

बस्ती को नई ग्राम पंचायत बनाने की उठी मांग

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण की मांग

डिंडौरी , नवभारत 16 जून। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

जनसुनवाई के दौरान 93 आवेदन प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदनों में संबल योजना की सहायता राशि, अनुग्रह सहायता, विद्युत बिल संबंधी शिकायत, सड़क निर्माण, नई ग्राम पंचायत गठन, आवागमन मार्ग, आगजनी से हुए नुकसान के मुआवजे तथा शासकीय योजनाओं में अनियमितता जैसे विषय प्रमुख रहे।

संबल योजना की सहायता राशि नहीं मिली

ग्राम अमरपुर निवासी जयंती धूमकेती ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके पति स्व.अनिल कुमार धूमकेती का निधन वर्ष 2024 में हो गया था। उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि हेतु आवेदन किया था, लेकिन अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की। जिस पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने संबंधित अधिकारी को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

विकास कार्य हो रहे प्रभावित

वनग्राम हथकटा के ग्रामीणों ने अपनी बस्ती को वर्तमान ग्राम पंचायत परसेल से पृथक कर नई ग्राम पंचायत गठित किए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत मुख्यालय की दूरी अधिक होने तथा बीच में वन क्षेत्र होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम गीधा, तहसील बजाग निवासी मनोज कुमार राजपूत ने अत्यधिक विद्युत बिल जारी होने की शिकायत दर्ज कराई।

चिंता | नए सत्र में फिर छात्रों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा, मार्ग पर हो गए बड़े बड़े गड्ढे

केंद्रीय विद्यालय का पहुंच मार्ग बना छात्रों के लिए मुसीबत

डिंडोरी, नवभारत 16 जून। जिले के प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय डिंडोरी तक पहुंचने वाला मार्ग एक बार फिर चर्चा में है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क की समस्या ने छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है।

शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने के लिए बच्चों को जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है, उसकी हालत आज भी बदहाल बनी हुई है। विद्यालय पहुंच मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड्ढे मौजूद हैं। हल्की बारिश होते ही ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बसों और पैदल आने-जाने वाले विद्यार्थियों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई

सबसे गंभीर बात यह है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस मार्ग की दुर्दशा लगातार समाचार पत्रों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में लाई जाती रही है। इसके बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। हर वर्ष बारिश के मौसम में यही समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।

सुगम और सुरक्षित होना चाहिए पहुंच मार्ग

अभिभावकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र अध्ययन करने आते हैं। ऐसे में विद्यालय का पहुंच मार्ग सुरक्षित और सुगम होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर जनहित का विषय माना जाना चाहिए। यदि समय रहते सड़क का निर्माण और गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी भी दिन गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है।

वर्षों से निभाई जा रही औपचारिकता

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। गड्ढों में मिट्टी या मुरुम डालकर खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन पहली ही बारिश में सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। नतीजतन सड़क फिर से पुराने हालात में पहुंच जाती है और लोगों की परेशानी जस की तस बनी रहती है।

बन सकता है बड़ी दुर्घटना का कारण

आम लोगों के बीच यह धारणा बन रही है कि शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपेक्षित गंभीरता नहीं मिल रही है। क्षेत्रवासियों, अभिभावकों और विद्यालय से जुड़े लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बारिश के मौसम को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। यदि प्रशासन अब भी नहीं जागा, तो आने वाले दिनों में यह अधूरा मार्ग किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।